

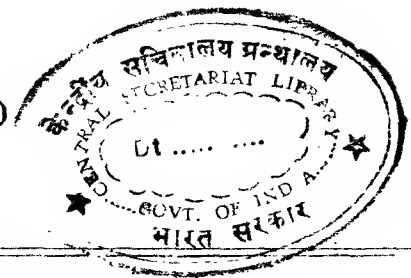


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 54]
No. 54]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 1990/माघ 23 1911
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 1990/MAGHA 23, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(विदेश कर प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1990

आयकर

सं. का. नि. 72(अ).—दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए
और आय पर करों की बाबत राज वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार और पोलैण्ड लोक गणराज्य की सरकार
के बीच इससे उपाबद्ध करार, उक्त करार के अनुच्छेद 30 के अनुसार
उक्त करार को प्रवर्तन में लाने के लिए, उनकी विधियों की अपेक्षाानुसार
दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अधिसूचना और प्रक्रियाओं के पूरा होने
की एक दूसरे को संसूचना के पश्चात् 26 अक्टूबर, 1989 को प्रवृत्त
हो गया है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का
43) की धारा 90 और कांजी (लभ) अतिकर अधिनियम, 1964
(1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत संघ
में प्रभावी किया जाएगा।

उपाबद्ध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और

राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

पोलैण्ड लोक गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और पोलैण्ड लोक गणराज्य की सरकार
ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा उन्हें
और अगे बढ़ाने की इच्छा से, और आय पर करों के संबंध में दोहरे

कराधान के परिहार और रोकथाम—अपवर्जन की रोकथाम के लिए एक करार सम्पन्न करने का निर्णय लेकर नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :—

(क) भारत में :

- (1) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर और उस पर लगाया जाने वाला कोई अधिभार ;
- (2) कम्पनी (लाभ) अतिरिक्त कर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत लगाया जाने वाला अतिरिक्त (जिन्हें इसमें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)।

(ख) पोलैण्ड में :

- (1) आयकर (पोडटेक डेचोडोकी);
- (2) मजदूरी और वेतन पर कर (पोडटेक ओड पाइनप्रोड्जैन्);
- (3) समता कर (पोडटेक वाइरड्वनावजी); और
- (4) कृषिकर (पोडटेक रोलनी); (जिन्हें इसमें इसके बाद "पोलिश कर" कहा जाएगा)।

2. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख के पश्चात् पैराग्राफ-1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने अपने ऐसे कराधान कानूनों में किए गए हों, जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद 3

समान परिभाषाएँ

1. इस करार में, जब तक विषयगत पठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :—

“(क) “भारत” राज्य से अभिप्राय है भारत गणराज्य और जब इसका प्रयोग भौगोलिक विचार से किया जाए तो इससे अभिप्राय है भारत गणराज्य का राज्य क्षेत्र और भारत गणराज्य के समुद्रवर्ती राज्य क्षेत्र का निकटवर्ती कोई समुद्रीय क्षेत्र जिस पर भारतीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत की प्रभुसत्ता हो अथवा प्रभुसत्ता संबंधी तथा संपूर्ण अधिकार हों।”

(ख) “पोलैण्ड” शब्द से अभिप्राय है पोलैण्ड लोक गणराज्य और जब इसका प्रयोग भौगोलिक विचार से किया जाए तो उससे अभिप्राय है पोलैण्ड लोक गणराज्य और पोलैण्ड लोक गणराज्य के समुद्रवर्ती राज्य क्षेत्र का निकटवर्ती कोई समुद्रीय क्षेत्र जिस पर पोलैण्ड लोक गणराज्य के कानूनों और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार पोलैण्ड लोक गणराज्य की प्रभुसत्ता या प्रभुसत्ता संबंधी तथा संपूर्ण अधिकार हों।”

“(ग) “एक संविदाकारी राज्य” और “दूसरा संविदाकारी राज्य” पदों का आशय विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार “भारत” या “पोलैण्ड” से है;

(घ) “1-2” शब्द का आशय, विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा पोलिश कर से है परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी बूक अथवा भूत के संदर्भ में देय हो जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाया गया कोई अर्थदण्ड हो;

(ङ) “व्यक्ति” शब्द में व्यक्ति, कंपनी और ऐसी कोई भी अन्य भत्ता शामिल है जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत कर लगने योग्य इकाई मानी जाती हो;

(च) “कंपनी” शब्द का आशय किसी भी ऐसे निर्गमित निकाय अथवा किसी भी ऐसी सत्ता से है, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अन्तर्गत कोई कंपनी अथवा निर्गमित निकाय के रूप में मानी जाती हो;

(छ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम” और “दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम” पदों का आशय क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम से है;

(ज) “सक्षम प्राधिकारी” शब्दों का आशय भारत के मामले में केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है; और पोलैण्ड के मामले में वित्त मंत्रों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से है;

(झ) “राष्ट्रिक” शब्द का आशय किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता धारण करने वाले किसी व्यक्ति और किसी भी ऐसे विधिक व्यक्ति, भागीदारों अथवा संस्था से है जिसे अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(ञ) “अन्तर्राष्ट्रीय यातायात” पद का आशय किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किसी जलयान अथवा वायुयान द्वारा की गई किसी दुलाई से है निवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, किसी गणवाचनों का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद 4

राजस्व प्रयोजन संबंधी निवाम स्थान

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, किसी “संविदाकारी राज्य का निवासी” पद का आशय किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिन पर, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा उस प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के आधार पर, वहां पर कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ-1 के उपबन्धों के कारण व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों में का निवासी हो तो उसकी हैमियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके

व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध बगिठतर हों। (महत्वपूर्ण द्वितीयों का केन्द्र);

- (ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उनके महत्वपूर्ण हिस्से निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास प्राप्त नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवास माना जाएगा जिसमें वह व्यावहारिक रूप से रहता हो;
- (ग) यदि उनका दोनों ही राज्यों में ऐसा आवास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में ऐसा आवास नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवास माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रपति है;
- (घ) यदि उपपैराग्राफ (क) से (ग) के उपबन्धों के अनुसार निवासस्थान का प्रश्न सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, तो संविदाकारी राज्यों के सभ्य प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. जहाँ किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ-1 के उपबन्धों के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस क़रार के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी संस्थापन" पद का अर्थ आरोबार के उस निश्चित स्थान से है जहाँ से उद्यम का आरोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्रबन्ध-व्यवस्था का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, तेल अथवा गैस-कूप, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई माल-गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएँ सौह्य करता हो;
- (ज) कोई फार्म, बागान अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, वनपालन, बागवानी अथवा तत्संबंधी कार्य किए जाते हों;
- (झ) कोई गरिसर जिसका प्रयोग विक्रय स्थल अथवा आदेश प्राप्त करने अथवा मंगवाने के लिए किया जाता हो;
- (ञ) कोई प्रतिष्ठान अथवा संरचना जिसा प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है;
- (ट) कोई वन स्थल अथवा कोई निर्माण-कार्य, प्रतिष्ठान अथवा संयोजन परियोजना (एसेम्बली प्रोजेक्ट) अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यक्रम, जहाँ ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यक्रम छः माह से अधिक चालू रहते हों।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होने हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा:—

- (क) उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;

(ख) केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संचालित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखना;

(घ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ आरोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;

(ङ) उद्यम के लिए, केवल विज्ञान सेवा सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ऐसे समान कार्यकलापों के संबंध में जो प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के हों; आरोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;

तथापि, उपपैराग्राफ (क) से (ङ) तक के उपबन्ध वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ उक्त उपपैराग्राफों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम द्वारा आरोबार का कोई अन्य निश्चित स्थान रखा जात हो।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, जहाँ किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा है तो उस उद्यम का प्रयोजन-स्थित राज्य में उस स्थिति में एक स्थायी संस्थापन होना माना जाएगा, यदि—

(क) उसे राज्य में उद्यम की ओर से संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह व्यावहारिक रूप से उस प्राधिकार प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यक्रमों उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तु खरीदने तक हो सम्मिलित नहीं हों;

(ख) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार न हो, परन्तु वह प्रथमतः राज्य में व्यावहारिक रूप से माल अथवा पण्य वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उस उद्यम की ओर से माल और पण्य वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, समन्वय कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से आरोबार करता है, बशर्ते ऐसे व्यक्ति अपने आरोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। लेकिन, जब किसी ऐसे एजेंट के कार्यक्रम पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से किए जाते हों जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हों, उस उद्यम द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसी तरह के सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

6. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) आरोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

प्रचल सम्पत्ति से अर्थ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित प्रचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वनिकी सहित) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "अचल संपत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानून के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में शामिल नहीं है—अचल संपत्ति के अन्वयार्थ के रूप में संज्ञा, कृषि और वनिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपकरण, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हैं, अचल संपत्ति के भांति के अधिकार और खनिज भण्डार, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार से प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अर्थागतों के अधिकार जलयन निकास तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं मने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबन्ध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार के लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ मना जा सकता है—

(क) उस स्थायी संस्थापन;

(ख) उस दूसरे राज्य में एक-समान अथवा उससे मिलते-जुलते मूल अथवा पण्य वस्तुओं की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है; अथवा

(ग) उस दूसरे राज्य में कारोबार संबंधी किए जाने वाले एक समान अन्य कार्यकलाप अथवा उससे मिलते-जुलते कार्यकलाप, जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से किए जाते हैं।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य को कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिये कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलते-जुलते परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता है और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है। किसी भी हालत में जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण लाभों की सही राशि का निर्धारण करना संभव नहीं है अथवा उसके निर्धारण में असाधारण कठिनाइयाँ आती हैं तो स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों की गणना किसी उचित आधार पर की जाए।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में, वे व्यय का कटौतियों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी अथवा तथा प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे जो उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार हों, और उनको परिधि के अन्दर आते हों, फिर वही वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों। किन्तु, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) को पेटेंटों, जानकारी

अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले रायलिटीज कोशों अथवा ऐसा हा अन्य अर्थागतों के तौर पर अथवा का गई विनिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध-व्यवस्था के लिए करीबन अथवा अन्य प्रभावों के तौर पर, अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में यदि कोई रकम अंश को गई हो तो उनके संबंध में ऐसा किया कठोरी को रक्षा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते में, उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय के स्थायी संस्थापन द्वारा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के उपयोग के बदले रायलिटीज, फार्मों अथवा ऐसा हा अथवा प्रयोगों के रूप में की गई विनिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध व्यवस्था के लिए करीबन अथवा अन्य प्रभावों के रूप में, अथवा किसी बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) को प्रभावित को गई हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति में निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहां लाभों में आय का वे मर्द शामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों में प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिवहन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिवहन एजेंसी में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वायुयान परिवहन से संबंधित विधियों पर व्याज को ऐसे वायुयान के परिवहन से प्राप्त लाभ माना जाएगा, तथा अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे व्याज के मामले में लागू नहीं होंगे।

4. "वायुयान-परिवहन" पद से तात्पर्य होगा—वायुयान के मालिकों या पट्टेदारों अथवा विक्रेताओं द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल का वायुयान द्वारा परिवहन करने का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों को और से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का आनुषंगिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्ष संबंधित कोई अन्य कार्यकारी शामिल हैं।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जहाजरानी के प्रचालन से अर्जित लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा जिनमें उद्यम के वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है।

2. यदि अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जहाजरानी का कार्य कर रहे किसी जहाजरानी उद्यम का वास्तविक प्रबंध-व्यवस्था का स्थान किसी जलयान में हो तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें उस जलयान का अपना बंदरगाह स्थित है, अथवा यदि उस जलयान का अपना ऐसा कोई बंदरगाह नहीं है तो उसे उस संविदाकारी

राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें उस जलधन का संचालन निवृत्त हो।

3. किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन अधिकरण में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर पैरा 1 के उद्देश्य भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और जहाजराता के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत सरकार और पोलैंड लोक गणराज्य की सरकार के बीच हुए दिनांक 27 जून, 1960 के करार के अनुच्छेद VIII में शामिल बातों के होते हुए भी, किमो संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्य संविदाकारी राज्य की बंदरगाह से तीसरे देशों की बंदरगाहों के बीच जलयानों के संचालन में प्राप्त आय पर उक्त दूसरे राज्य में कर लगाया लेकिन उक्त दूसरे राज्य में लगाए गए कर को उसके 50 प्रतिशत तक राशि के बराबर कम कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद-10

सहयोगी उद्यम

जहाँ :

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का प्रबंध-व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भाग लेना है; अथवा

(ख) वे दो व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को प्रबंध-व्यवस्था नियंत्रण या पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखा अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण, उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य को निवासी किमो कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता है।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लग सकता है जिस राज्य की लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जहाँ ऐसे लाभांश इस करार के प्रवृत्त होने के बाद किए गए अंशदानों से संबंधित होते हैं।

यह पैराग्राफ ऐसे लाभांशों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ है शेषों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय, जो ऋण-दावे नहीं हों, लाभों

में सम्मिलित हों, तथा अन्य निम्नलिखित अधिकारों के अन्तर्गत आय पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों द्वारा मृत्यु के समय आय पर लागू होती है, जिन राज्य के वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने

के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान में उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता हो और वह सम्पत्ति, जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावों हर से संबंधित हों। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 और 16 के उद्देश्य परावृत्ति होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य को निवासी है और वह दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती वहाँ वह दूसरा राज्य, कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगायेगा जहाँ तक कि उस दूसरे राज्य के, किना निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा नहीं किए जाते अथवा जहाँ तक कि वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जाते हैं, उन दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं हैं अथवा कम्पनी के अवितरित लाभों पर लगाया जा रखने वाला कर नहीं लगाया जाएगा चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 12

व्याज

1. संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. किन्तु, इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उक्त राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह अर्जित होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रसारित कर, व्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी—

(क) एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले व्याज पर उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो या उनका उक्त पर हितभोगी स्वामित्व हो:

(1) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(2) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक।

(ख) एक संविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले व्याज को उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी यदि उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी का हितभोगी स्वामित्व हो और वह निम्नलिखित द्वारा दिए गए अथवा समर्थित ऋण अथवा उधार के संबंध में प्राप्त किया जाता हो;

(1) पोलैंड के मामले में, बक हेंडलोवी डब्ल्यू वारशबीची एस.ए. जिस सीमा तक ऐसा व्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्त-व्यवस्था करने के कारण होता है;

(2) भारत के मामले में, भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एजिजम बैंक), जिस सीमा तक ऐसा व्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्त व्यवस्था करने के कारण होता है;

(3) किसी संविदाकारी राज्य के विदेश व्यापार की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था करने वाला कोई भी संस्थान;

- (4) कोई अन्य व्यक्ति बशर्ते कि ऋण अथवा उधार प्रथमो-
लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित
हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज" शब्द का अर्थ प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधों दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिलूत हो अथवा नहीं और चाहे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और खास तौर पर सरकारी प्रति-भूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों, जिनमें ऐसी प्रति-भूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त आय। विलम्बित अदायगी के लिए अर्बुद संबंधी प्रसारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए व्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याही का हितभोगी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज अर्जा हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अर्जा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज, उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि व्याज अर्दा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-भाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां व्याज अर्दा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो, अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गयी है, और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, व्याज अर्दा करने वाले और हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण, अर्दा की गयी व्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की रकम अर्दा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अर्दा करने वाले और हितभोगी स्वामी के बीच सद्मति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक प्रयोजन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अर्दा की गयी रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. लेकिन, इस प्रकार कर रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये उत्पन्न हुए हों। परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभोगी स्वामी हो तो उस प्रकार प्रभावित, कर, रायल्टियों अथवा

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 22.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियों" शब्द का अर्थ किसी साहित्यिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक कृतियों, जिनमें चलचित्र फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए टेपों के प्रति-निष्पाधिकार, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिज़ाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग के लिए, अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उद्देश्य, अथवा आर्थिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिकूल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी;

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अर्थ प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कर्मियों के सेवाओं का व्यवस्था भी शामिल है, के प्रतिकूल में अदायगियों करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को की गई अदायगियों से मिन, कितो भी व्यक्ति को की गयी कितो भी रकम की अदायगियां।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभोगी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित कितो निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है तथा वह अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा, जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अर्दा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएगी यदि अर्दा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-भाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हों। परन्तु, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अर्दा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अर्दा करने की देनदारी उत्पन्न हुई हो, तथा ऐसी रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां अर्दा करने वाली तथा हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विशिष्ट संबंध होने के कारण रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए अर्दा की गई फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अर्दा की गई होती, तो वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम-वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों की रकम का अतिरिक्त भाग इस करार के अन्य उपबंधों को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाये जाने योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 14

पूँजी प्रभिलाष

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 13 अंतर्निहित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अथवा सम्पत्ति के

अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलेखों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त हुए अभिलेखों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के स्थायी संस्थापन का व्यापारिक सम्पत्ति का भाग है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति हो, जिनमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले ऐसे अभिलेख भी शामिल हैं, उन पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति, के अंतरण से प्राप्त अभिलेखों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अंतरणकर्ता निवासी है।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूंजीगत स्टाक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलेखों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रधानतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. किसी ऐसी कम्पनी में पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलेखों पर, जो किसी संविदाकारी राज्य की निवासी हो, उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलेखों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी व्यावसायिक है, सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कराधेय होगी :—

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की उसकी अवधि अथवा अवधियों उस दूसरे राज्य के संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में जैसा भी मामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हो, तो उस मामले में उक्त आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र "ज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, न्याय-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दन्त-चिकित्सकों तथा सेवाप्राप्तों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रयोज्यलिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :—

(क) प्राप्तकर्ता संगत "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो;

(ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक नियोजक के किसी ऐसे स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया गया हो, जो दूसरे राज्य में स्थित है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के संचालन में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 17

निदेशकों की फीस तथा उच्च स्तरीय प्रबंधकीय

अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक-मंडल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उससे मिलती-जुलती अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी ऐसी कम्पनी के, जो दूसरे राज्य की निवासी है, उच्च स्तरीय प्रबंधकीय पद पर नियुक्त कर्मचारी की हैसियत से प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा उससे मिलते-जुलते पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 18

मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि एक थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्य-कलापों से, जिन्हें वह दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लग सके।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा इस प्रकार की अपनी हैसियत में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में

उद्भूत होने वाली आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, वहां अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उक्त मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए गए हों।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों से अर्जित आय प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही करयोग्य होगी, यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यक्रम दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा स्वीकृत सांस्कृतिक अथवा खेल-कूद कार्यक्रम के आदान-प्रदान के दायरे में आते हैं और जिसमें उनके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित होते हैं।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियत में एक संविदाकारी राज्य में किए गए व्यक्तिगत कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी का स्वयं प्राप्त नहीं होती है परंतु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह आय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही करयोग्य होगी, यदि उस दूसरे व्यक्ति के कार्यक्रम दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा स्वीकृत सांस्कृतिक अथवा खेल-कूद कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के दायरे में आते हैं, उस दूसरे राज्य की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया हो जिसमें उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए किसी सरकारी स्वरूप की स्वीकृतियों के निर्वाह में की गई सेवाओं के संबंध में प्रदत्त पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लग सकेगा।

(ख) लेकिन, ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में प्रदान जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो:

- (1) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा
- (2) मात्र सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना था।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा सृजित किए गए कोष में से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में करयोग्य हो सकेगी यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य का कोई निवासी है तथा उसका एक-राष्ट्रिक है।

3. अनुच्छेद 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लगू होंगे।

अनुच्छेद 20

गैर-सरकारी पेंशन तथा वाविकी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न किसी अन्य पेंशन पर, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में आंतरिक स्त्रोतों से प्राप्त हुई हो, केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर सकेगा।

2. "पेंशन" शब्द का अर्थ है पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान चोटग्रस्त होने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में की गई कोई आवधिक अदायगी।

3. "वाविकी" शब्द का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के किसी दायित्व के अग्रतः जीवन-वर्धित अथवा किसी विनिश्चित या निश्चित समयवधि के दौरान नियत अवधि पर समय-समय पर देय हो।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. ऐसी अदायगियों पर, जिन पर कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु, जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने के नुरंत पहले किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी जीविका, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रथम उल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उस राज्य में कर नहीं लगाया जा सकेगा बशर्त कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोत से उद्भूत होती हों।

2. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु द्वारा किसी ऐसे संविदाकारी राज्य में, जिसमें वह मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, किए गए कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त आय उस राज्य में करयोग्य नहीं होगी जब तक कि यह राशि उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक राशि से अधिक न हो।

3. उस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि तक के लिए बढ़ाया जाएगा जो शिक्षा अथवा शुरू किए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परंतु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस के प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

4. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 22 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उन संविदाकारी राज्य का उस "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा तत्काल पूर्ववर्ती "पिछले वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में निवासी रहा हो।

अनुच्छेद 22

प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा शोध छात्रों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन कार्य अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा था, ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए किसी भी पारिश्रमिक पर उन दूसरे राज्य में उसके पहुंचने की तारीख से अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगा।

2. यह अनुच्छेद शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य जन-हित में नहीं है बल्कि मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिये है।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "मान्यता प्राप्त संस्था" का अर्थ ऐसी संस्था से है जिससे संबंधित संविदाकारी राज्य के सभ्य प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद—23

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहने हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की वे मदें, जहां-कहीं उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाने योग्य होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारवार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता है और जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में आय धरा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय को उन मदों पर, जिनका इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

4. संविदाकारी राज्यों के सभ्य प्राधिकारी पूर्वोक्त पैराग्राफों के अनुसार किनो करार के होने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। सभ्य प्राधिकारी विचार-विमर्श के द्वारा इस अनुच्छेद में दिए गए पारस्परिक करार प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु, समुचित द्विपक्षीय प्रक्रियाओं, शर्तों, पद्धतियों और कार्य-पद्धतियों का विकास करेंगे।

अनुच्छेद—24

दोहरे कराधान की समाप्ति

1. दोनों ही संविदाकारी राज्यों में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को शामिल करने रहेंगे सिवाय उनके कि जहां इस करार में उनके प्रतिकूल कोई उपबंध बनाए जाने है।

2. दोनों संविदाकारी राज्यों में दोहरे कराधान का परिहार निम्न-लिखित तरीके से किया जाएगा:—

(क) जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर, इस करार के उपबंधों के अनुसार, दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, वहां प्रयोज्य लिखित राज्य, इस पैराग्राफ के उप-पैरा (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी आय को कर में छूट दे सकता है परन्तु उस व्यक्ति का शेष आय पर कर को संगणना करने में कर की वह दर लागू कर सकता है जो उस स्थिति में लागू होती यदि छूट-प्राप्त आय पर इस प्रकार की छूट नहीं दी गई होती।

(ख) दोनों ही संविदाकारी राज्य अपने निवासियों पर कर लगाने समय, कर के उस आधार में जिस पर इस प्रकार के कर लगाए जाने हैं, आय की उन मदों को शामिल कर सकेंगे जिन पर इस करार के अनुच्छेद 11, 12 और 13 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है लेकिन ऐसे आधार पर संगणित कर की राशि में से दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा की गई कर की राशि के बराबर की कटौती देंगे। तथापि, ऐसी कटौती प्रयोज्य लिखित राज्य द्वारा लगाए जाने योग्य कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसकी कटौती मंजूर करने से पहले संगणित किया गया हो, जो उस आय के अनुकूल हो जिस पर इस करार के अनुच्छेद 11, 12 और 13 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ख) के प्रयोजनार्थ "दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किया गया कर" पदावली में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गई मानी जाएगी जो दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त आय के कराधान से संबंधित कानूनों के अंतर्गत कर लगाने योग्य आय की संगणना करने में अनुमत कटौती अथवा छूट अथवा कर की कटौती अथवा अन्यथा रूप में किसी राहत के नहीं होने की स्थिति में देय होगी।

अनुच्छेद 25

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में अथवा वैसी ही शर्तों के अधीन लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसी कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में उन्हीं परिस्थितियों में तथा वैसी ही शर्तों के अधीन उसी तरह के कार्यकलाप करने वाले उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक संविदाकारी राज्य को, कराधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य के अनिवासी व्यष्टियों को कोई ऐसी वैयक्तिक छूट, राहत, कटौतियां तथा कटौतियां प्रदान करने के लिए बाध्य करता है जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को ही उपलब्ध हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रयोज्य लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रयोज्य लिखित राज्य के अन्य वैसी ही उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों तथा वैसी ही शर्तों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में, "कराधान" पद का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

6. उन मामलों की छोड़कर जिनमें इस करार के अनुच्छेद-11, अनुच्छेद-12 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे

संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया भ्रष्टाचार, रायल्टिय और अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कर लगाने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे, जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए थे। इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिए गए कोई ऋण, ऐसे उद्यम की कर लगाने योग्य पूंजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन्हीं समान शर्तों के अधीन कटौती पाने योग्य होंगे जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अनुबंधित किए गए थे।

7. दोनों संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत कराधान प्रयोजनों के लिए उपलब्ध छूटों, राहतों, कटौतियों, घटौतियों और मोक पर इस करार के किसी उपबंध से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस करार के अनुरूप नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह मामला, उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिसके कारण ऐसा कर लगाया गया हो जो : करार के अनुरूप नहीं हो।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। जो भी करार हो गया हो, उसे संविदाकारी राज्यों के कानूनों में निहित किसी भी समय-सोमा के होने के बावजूद भी कार्यान्वित किया जाएगा।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा संकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर सकेंगे जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अधिप्राय के अंतर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधा पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत होता हो, वहाँ ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का (जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं) आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों के अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहाँ तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान-व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जासबाजी अथवा अपवर्धन को रोकने के लिए करार के प्रतिकूल नहीं हो। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई

कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन, यदि उक्त सूचना को, सूचना भेजने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अन्तर्गस्त हों, जो इस करार के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे उक्त सूचना को सार्वजनिक तौर पर स्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी, विचार-निर्णय के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समचित श्रेतों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें, जहाँ-कहीं उपयुक्त हो, कर के परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा किन्हीं विशिष्ट मामलों में अनुरोध मिलने पर अथवा दोनों तरह से किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर परस्पर यह तय करेंगे कि किस-किस सूचना का या किन-किन दस्तावेजों का नेमी आधार पर आदान-प्रदान किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे एक संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं:—

- (क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक परिपटी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सफ़ाई करना जो उस राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो सकते;
- (ग) कोई ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सफ़ाई करना जिससे कोई व्यापारिक व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक भेद खुल जाएगा अथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

अनुच्छेद 28

कर-वसूली में सहयोग

1. संविदाकारी राज्य इस करार से संबंधित करों की वसूली में उन मामलों में एक-दूसरे राज्य की मदद करने और समर्थन देने का जिम्मा लेते हैं, जहाँ अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार, कर निश्चित रूप से देय हैं।

2. वसूली के प्रवर्तन के किसी अनुरोध के मामले में किसी भी संविदाकारी राज्य के कर संबंधी दावों को, जिनका अन्तिम रूप से पता लगाया जा चुका है उसे दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रवर्तन के लिए स्वीकार किया जाएगा जिससे अनुरोध किया गया है, और उनकी वसूली, उस राज्य के करों के प्रवर्तन और उनकी वसूली हेतु लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी।

3. भारतीय कर के मामले में अनुरोधपत्र को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय, भारत द्वारा वित्त मंत्री पोलैण्ड अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पास भेजा जाएगा और उनके साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न होगा जैसा कि भारत के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करों का अंतिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे करदाता द्वारा देय हैं।

4. पोलैण्ड कर के मामले में, अनुरोधित वित्त मंत्री, पोलैण्ड अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के पास भेजा जाएगा और उसके साथ ऐसा प्रमाण-पत्र संलग्न होगा कि पोलैण्ड के कानूनों में यह स्थापित करने के लिए अपेक्षित है कि करों का अंतिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है और वे कारदाता द्वारा देय हैं।

5. जहां कर संबंधी दावा इस संबंध में आपत्ति किए जाने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण निर्धार नहीं होता, वहां एक संविदाकारी राज्य अपने राजस्व को बचाने के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य से उसके बारे में ऐसे अंतरिम उपाय करने का अनुरोध कर सकता है जो उसके दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत इस तरह वैध हैं।

6. किसी करदाता से प्राप्त करों की वसूली में सहायता के लिए अनुरोध तभी किया जाएगा जब अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस करदाता से कर वसूल करने के लिए उसकी पर्याप्त परिपक्वता उपलब्ध न हो।

7. जिस संविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 5 के अनुसरण में कर वसूल किया जाता है, वह राज्य इस प्रकार वसूल की गई रकम को तत्पश्चात् तुरन्त दूसरे संविदाकारी राज्य को भेजेगा, जिसने अनुरोध किया था।

अनुच्छेद 29

राजनयिक तथा कौमुली कार्यकलाप

इस करार में निहित किसी व्यवस्था का, अन्तरराष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपायों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौमुली अधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई-प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 30

प्रवर्तन

प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को इस करार को प्रवर्तित करने के लिए उसके कानून के अधीन अपेक्षित कार्यविधियों के पुरा हो जाने के बारे में अधिसूचित करेगा। यह करार, इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और उसके बाद

(क) भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें बाद वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के, अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में,

(ख) पोलैण्ड में, उस कैलेंडर वर्ष के, जिसमें बाद वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में।

अनुच्छेद 31

समाप्ति

यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष के 30 जून को अथवा उसके पूर्व, राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकता है और ऐसी स्थिति में यह करार:

(क) भारत में जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले परिवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

(ख) पोलैण्ड में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परिवर्ती वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अग्रहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

बारसा में वर्ष एक हजार नौ सो नवासी के जून माह के 21वें दिन को हिन्दी पोलिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न किया गया, जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। हिन्दी और पोलिश पाठों में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ह./-

ह./-

(के. नटवर सिंह)

(टी. ओलेचोवस्की)

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

पोलैण्ड लोक गणराज्य
की सरकार की ओर से

[अधिसूचना सं. 8574/फा. सं. 501/8/79-एफ. टी. डी.]

पो. के. अण्णादू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1990

INCOME-TAX

G.S.R. 72(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of Republic of India and the Government of the Polish People's Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the 26th October, 1989, after the notification by both the Contracting States and communication to each other of the completion of procedures required under their laws for bringing into force of the said Agreement in accordance with Article 30 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

**ANNEXURE
AGREEMENT**

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDIA**

AND

**THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S
REPUBLIC**

FOR

**THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Polish People's Republic desiring to further develop and facilitate the economic relationship between the two countries, and having decided to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) in India :

(i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961;

(ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964;

(hereinafter referred to as "Indian tax").

(b) in Poland :

(i) the income tax (podatek dochodowy);

(ii) the tax on wages and salaries (podatek od wynagrodzen);

(iii) the equalisation tax (podatek wyrównawczy); and

(iv) the agriculture tax (podatek rolny);
(hereinafter referred to as "Polish tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws, which are the subject of this Agreement.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

- (a) the term 'India' means the Republic of India and when used in a geographical sense means the territory of the Republic of India and any maritime area adjacent to the territorial waters of the Republic of India within which, under the laws of India and in accordance with international law, the Republic of India has sovereignty or sovereign & exclusive rights.
- (b) the term 'Poland' means the Polish People's Republic and when used in a geographical sense means the territory of the Polish People's Republic and any maritime area adjacent to the territorial waters of the Polish People's Republic within which, under the laws of the Polish People's Republic and in accordance with international law, the Polish People's Republic has sovereignty or sovereign and exclusive rights.
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Poland, as the context requires;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Polish tax as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes :
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representatives and in the case of Poland the Minister of Finance or his authorised representative;
- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving the status from the laws in force in the Contracting State;

(j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

FISCAL RESIDENCE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if the question of residence cannot be determined according to the provisions of sub-paragraphs (a) to (c), the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

(h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;

(i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;

(j) an installation or structure used for the exploration of natural resources;

(k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities continue for a period of more than six months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

However, the provisions of sub-paragraph (a) to (e) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said subparagraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first mentioned State, if

- (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct for immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts if any, paid (other than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this Agreement, then the provisions of those articles shall not be affected by the provisions of this article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

1. Profits from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of an enterprise carrying on shipping in international traffic is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

4. Notwithstanding anything contained in paragraph 1 and Article VIII of the Agreement dated 27 June, 1960 between the Government of India

and the Government of the Polish People's Republic regarding shipping co-operation, income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships from the ports of the other Contracting State to the ports of third countries and from the ports of third countries to the ports of the other Contracting State may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other Contracting State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State of an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends where such dividends relate to contributions made after the entry into force of this Agreement.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, —

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

(i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or

(ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) Interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracting State and is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :

(i) in the case of Poland, Bank Handlowy Warszawski SA, to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;

(ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India (Exim Bank), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;

(iii) any institution of a Contracting State in charge of public financing of external trade;

(iv) any other person provided that the loan or credit is approved by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13**ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES**

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 22.5 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both

of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14**CAPITAL GAINS**

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in article 6, and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15**INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income" as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 17

DIRECTORS' FEES REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are within the framework of cultural or sports exchange programme agreed to by both Contracting States and are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if the activities of that other person are within the framework of cultural or sports exchange programme agreed to by both Contracting States and are supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

Article 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or a political sub-division or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of articles 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or local authority thereof.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Income derived by a student or business apprentice in respect of activities exercised in a Contracting State in which he is present solely for the purpose of his education or training, shall not be taxable in that State, unless it exceeds the amount necessary for his maintenance, education or training.

3. The benefits of this article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

4. For the purposes of this article and article 22, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".

Article 22

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State or any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other state.

2. This article shall not apply to income from research if such research is not in public interest but is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities shall through consultations develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this article.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In both the Contracting States, double taxation will be avoided in the following manner :

- (a) Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.
- (b) Either of the Contracting States when imposing taxes on its residents may include in the tax base upon which such taxes are imposed the items of income which according to the provisions of Articles 11, 12 and 13 of this Agreement may also be taxed in the other State but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in the other Contracting State. Such deduction shall not, however, exceed that part of tax leviable by the first-mentioned State, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which, in accordance with the provisions of Articles 11, 12 and 13 of this Agreement may be taxed in the other State.

3. For the purposes of sub-paragraph (b) of paragraph 2 the term "tax paid in the other Contracting State" shall be deemed to include any amount which have been payable as tax but for any relief by way of a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or a reduction of tax or otherwise under the laws relating to taxation of income in force in that other Contracting State.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation, and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on

enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. Nothing contained in this article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

6. Except where the provisions of Article 11, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 7 of Article 13 of this Agreement apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

7. The exemptions, reliefs, reductions, deductions and allowances for taxation purposes available under the domestic laws of the two Contracting States shall not be adversely affected by any provision of this Agreement.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the

competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

ASSISTANCE IN COLLECTION

1. The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Agreement relates, in the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the States making the request.

2. In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its taxes.

3. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, India to Minister of Finance, Poland or his authorised representative and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

5. In the case of Poland tax, the request will be sent by the Minister of Finance, Poland or his authorised representative to the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, India and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of Poland to establish that the taxes have been finally determined and are due from the taxpayer.

5. Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate assets of that taxpayer are not available for

recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request.

Article 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notification and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given;
- (b) in Poland in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in Poland, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at WARSAW this Twenty First day of June one thousand nine hundred and eighty nine in the Hindi, Polish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between the Hindi and Polish texts, the English text shall prevail.

Sd/-

(K. NATWAR SINGH)

For the Government of
the Republic of India.

Sd/-

(T. OLECHOWSKI)

For the Government
of the Polish People's
Republic.

[Notification No. 8574 F. No. 501/8/79-FTD]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.